भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1526
मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी

1526. श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऑटो मोबाइल क्षेत्र में मंदी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस देश में ऑटो मोबाइल हेतु मंदी को रोकने और मांग को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और(ख): पिछले कुछ महीनों से ऑटोमोटिव क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में आवर्ती मंदी है। मंदी के लिए अवधारणा संबंधी कारणों के साथ अनेक वित्तीय और विनियामक कारण है, जो निम्नानुसार हैं:

- ऑटो क्षेत्र में वित्त की उपलब्धता में कटौती।
- ढुलाई क्षमता को 25% तक बढ़ाकर वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक्सल भार क्षमता में बढ़ोतरी के कारण नए वाहन की मांग में गिरावट आई।
- तीन वर्षों (नई कारों) और पाँच वर्षों (नई दुपहिया वाहन) के लिए दीर्घावधिक तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम के अपफ्रंट संग्रहण के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण वाहन की कीमत में बढ़ोतरी।
- डीलरों के लिए 25% से 60% तक कोलेट्रल में बढ़ोतरी के कारण डीलरों के इनवेंट्री वित्त में कमी।
- बीएस-IV मानकों वाले स्टॉक को बेचने के लिए ओईएम द्वारा छूट के कारण खरीद को स्थगित करना (बीएस-III से बीएस-IV में परिवर्तन के समय यही कारण था)।

(ग) एक नीति निर्माता के रूप में, सरकार ऑटो सेक्टर के व्यापक और निरन्तर विकास के लिए आवश्यकतानुसार उपाय के पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने और विकास हेतु सदैव प्रयास करती है। ऑटोमोबाइल मंदी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- कॉर्पोरेट कर में 22% की कमी।
- आईसीई और ईवी की भविष्य में पंजीकरण की निरंतरता।
- स्क्रैपेज नीति विचाराधीन।
- जून, 2020 तक नई कारों के पंजीकरण में प्रस्तावित वृद्धि स्थगित।
- पीएसयू बैंकों को ₹70,000 करोड़ की राशि जारी की गई।
- खरीदे गए वाहन के लिए रेपो दर को ब्याज से जोड़ना।

*****